शोध मंथन Vol. XVI No.4 Oct.- Dec. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.103

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः समग्र शिक्षा एवं पाठ्यपुस्तक का प्रश्न (प्रारम्भिक विद्यालयी शिक्षा के विशेष संदर्भ में)

प्राप्तिः 14.12.25
स्वीकृतः 24-12-25

103

डॉ. ममता कुमारी
सहायक प्राध्यापक
शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
ईमेलः *mtamta@uou.ac.in*

सारांश

यह तथ्य महत्वपूर्ण और स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षित संवेदना संपन्न एवं विचारवान नागरिक का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नागरिक का शिक्षित होना, उसकी शिक्षा का उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक होना तथा इस विकास का निरंतर परिमार्जन होते रहना भी अति आवश्यक है। शिक्षा रोजगार का माध्यम मानी जाती है, लेकिन शिक्षा का एक समग्र रूप भी है। शिक्षा के इसी सर्व समावेशी रूप को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विश्व में शिक्षा, मनोविज्ञान, साहित्य और सामाजिकी जैसे विषयों के अंतरविषयी अध्ययनों की श्रृंखला दृष्टिगोचर होती है । निरंतर अध्ययन, शोध एवं प्रयोगात्मक कार्यकलापों से शिक्षा के ऐसी सर्व समावेशी रूप की अवधारणा प्राप्त होती रही है। भारतीय संदर्भ में भी इस प्रक्रिया के अलग–अलग चरण देखने को मिलते हैं। 2020 में प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी ही अवधारणा का विकास करती है । शिक्षा, शिक्षक, शिक्षण, छात्रशिक्षा के विभिन्न स्तर एवं माध्यम पर विचार करते हुए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को एक नए आकार में ढालने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध–पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयी स्तर पर समग्र शिक्षा तथा पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में अपना अध्ययन प्रस्तुत कर रहा है Social and emotional learning SEL.

मुख्य शब्द

समग्र शिक्षा, टैक्सोनॉमी, Curriculum, Holistic, Paradigm shift, SEL (Social and emotional learning), समावेषी शिक्षा, Unschooling, औपनिवेशिक।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 विधिवत क्रियान्वयन से पूर्व श्री कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने वर्ष 2019 में जो प्रारूप भारत सरकार को प्रेषित किया था उसकी प्रस्तावना में स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा गया था, "शिक्षा सूचना और जानकारी मात्र नहीं है, जिसे आपके

मस्तिष्क में डालकर वहां कोलाहल पैदा की जाती है, और जो आपको जीवन भर समझ में नहीं आता। हमारे पास जीवन निर्माण, आदमी बनाने, विचारों को आत्मसात करने वाला चरित्र होना चाहिए। यदि आपने पांच विचारों को आत्मसात किया है और उनको अपना जीवन और किरदार बनाया है तो आपके पास हर उसे व्यक्ति के बनिस्बत अधिक शिक्षा है जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया है। यदि शिक्षा सूचनाओं/जानकारी के समान होती तो पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़ी ज्ञानी है और एनसाइक्लोपीडिया सबसे महान ऋषि है''।

यह आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के प्रभावशाली सिद्धांतकार रैल्फ टाइलर[1] ने भी 1956 में शिक्षा की इसी चरित्रगत विशेषता को परिरक्षित किया था। टाइलर ने कहा "शिक्षा शिक्षार्थी के व्यवहार को बदलने की प्रक्रिया है"। "Education is the process of changing the behaviour of learners through plant learning experience" (Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago, University of Chicago press, 1950) आधुनिक भारतीय ऋषि और विचारक स्वामी विवेकानंद और अमेरिकी शिक्षाविद रैल्फ टाइलर के विचारों की यह समानता आश्चर्यचकित तो करती ही है, लेकिन साथ ही साधारण विद्यार्थी के लिए शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस बात को भी सामने लाती। रैल्फ टाइलर और उनके सहयोगियों के सिद्धांत की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रो0 कृष्ण कुमार लिखते हैं, "रैल्फ टाइलर के Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago, University of Chicago press, 1950 का प्रभाव पूरे विश्व में हुआ और भारत में आज भी शिक्षा के ऐसे स्नातकोत्तर छात्र और प्रोफेसर मिल जाते हैं, जो टाइलर का नाम लिए बिना उनकी शिक्षा की परिभाषा का उपयोग करते हैं। शिक्षा तथा पाठ्यक्रम को मनोविज्ञान के अधिकार क्षेत्र में रखने वाली यह परिभाषा इस प्रकार है– 'शिक्षा लोगों के व्यवहार के प्रतिमानों को बदलने की प्रक्रिया है'। टाइलर ने व्यवहार पर जो जोर दिया उसका विकास टैक्सोनॉमी ऑफ एजूकेशन ऑब्जेक्टिव (न्यूयॉर्क, डेविड मके, 1956) में हुआ था। इसे बेंजमन ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने तैयार किया और भारत में षिक्षा पर होने वाली चर्चाओं में इसका आज भी हवाला दिया जाता है"[2]।

अपनी इस बात को भारतीय संदर्भ में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर कृष्ण कुमार लिखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCRT) की स्थापना 60 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसके अनेक शिक्षाशास्त्रियों ने अमेरिका में उस समय प्रशिक्षण पाया था, जब वहाँ ब्लूम के व्यवहारात्मक उद्देश्य बेहद लोकप्रिय थे ब्लूम की टैक्सोनॉमी (वर्गीकरण विज्ञान) रैल्फ टाइलर को समर्पित है जिसकी पाठ्यक्रम विकास विषयक पुस्तक का शिक्षाशास्त्र के छात्रों की पाठ्यपुस्तक के रूप में अमेरिका तथा भारत दोनों ही जगह में अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है"[3]। दोनों ही उद्धरणों को ध्यान से पढ़ने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ही विचारक विद्यार्थी के व्यावहारिक ज्ञान एवं समाजोपयोगी संवेदना के विकास के आधार पर शिक्षा एवं ज्ञान की उपयोगिता को तय करने पर जोर दे रहे हैं। यदि विद्यार्थी को प्रदान की जा रही शिक्षा विद्यार्थी की व्यावहारिक संवेदनात्मक प्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में अक्षम है तो वैसी शिक्षा मात्र, आंकड़ों, तिथियों, सिद्धांतों और विभिन्न विषयों के व्यावहारिक बोझ का प्रतिबिंब मात्र बनकर रह जाती है। ऐसी शिक्षा तरह–तरह की सूचनाओं और सिद्धांतों का एक विस्फोट तो कर सकती है परंतु विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर, संवेदना

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.103

एवं ज्ञान तंत्र पर दूरगामी प्रभाव डालने में अक्षम सिद्ध होती है, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी की भावी जीवन में आने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक जीवन की दैनिक समस्याओं को हल करने में भी असफल होगी।

निश्चित ही यह एक गंभीर प्रश्न है। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई, 2020 को की गई। इस नीति का देशभर में स्वागत किया गया। .....स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। प्रथम नीति 1968 में, दूसरी नीति 1986 में और तीसरी नीति 2020 में प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार शिक्षा में सुधार एवं परिवर्तन हेतु 1948 में राधा कृष्ण आयोग, 1952 में मुरलियार आयोग, 1964 में कोठारी आयोग के साथ–साथ समय–समय पर कई समितियां एवं समूह आदि का गठन किया गया था। उन्होंने कई मूल्यवान अनुशंसाएं भी दी थी, परंतु दुर्भाग्य से इच्छा शक्ति के अभाव में इनको क्रियान्वित नहीं किया जा सका या बहुत अल्प मात्रा में ही किया गया, जिस कारण से हमारी शिक्षा की गुणवत्ता दिनों दिन खराब होती गई"[4]।

निश्चित ही यह एक सामान्य विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 गहन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण की मांग करती है। यह विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ समझना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि, 'हमारी शिक्षा कैसी हो'? 'पाठ्यक्रम कैसे हों'? 'पाठ्य पुस्तक कैसी हो'? इन प्रश्नों और समस्याओं पर विचार करते हुए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के विशेषज्ञों की कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर संबंधों पर बात करते हुए श्री देशराज शर्मा ने हमारा ध्यान कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ खींचा है। श्री शर्मा लिखते हैं, "प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे सीखने की नींव कहा गया है से जुड़ी संस्तुतियां शिक्षा जगत के सम्मुख कई चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगी। जैसे दूरदराज तथा कठिन क्षेत्र में इसे लागू करना भी एक चुनौती होगी। एक अनुमान के अनुसार देश में 13.77 लाख आंगनबाड़ियों में 12.5 लाख कर्मी तथा 11.6 लाख सहायक कर्मी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रांत में ही 80160 आंगनबाड़ियाँ व 12070 उप–आंगनबाड़ियाँ हैं। गैर सरकारी समाज के सहयोग से संचालित विद्या भारती द्वारा संचालित देशभर की शिशु वाटिकाओं में 6 लाख से अधिक बच्चे अंकित हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार अभी तक देश में 362940 आंगनबाड़ियों में शौचालय उपलब्ध नहीं है इसी तरह 159568 आंगनबाड़ियों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अनुसार देश में 46.6 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। दुनिया में कुपोषण की दृष्टि से हम तीसरे स्थान पर हैं"[5]। श्री देशराज ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष प्रस्तुत कई गंभीर समस्याओं में से सिर्फ एक की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान में संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था पूर्व विद्यालयी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के अनेकों आयाम के साथ संचालित हो रही हैं। ऐसे परिदृश्य में राष्ट्रीय शैक्षिक पटल पर विचार करना न केवल चुनौती पूर्ण है, अपितु नितांत समस्यापरक भी।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के आलोक में विद्यार्थी के समग्र विकास एवं पाठ्यक्रम के महत्व तथा साथ ही ऐसे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न का अध्ययन करना है। कहना ना होगा कि विद्यार्थी को पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए सर्वाधिक

महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। साथ ही हमको यह भी ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी स्तर में विद्यार्थी के समावेशी उन्नयन को ही ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किए गए अध्ययन हमें इस विषय में यही जानकारी देते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 समाज के सभी वर्गों के उन्नयन एवं समग्र विकास को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है। इसका मूल उद्देश्य Holistic (सर्वांगीण) शिक्षा है। यह किसी भी विद्यार्थी के शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है। डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया ने लिखा है, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 शिक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है। इसमें गुणवत्ता पर तो सर्वाधिक बल दिया गया है, साथ ही शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों की चिंता भी की गई है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक एवं समाज के हितों को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रहितों को सर्वोपरि मानकर इस शिक्षा नीति को निर्मित किया गया है। इसमें समाज के विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, समाज सेवी, क्रीड़ा, कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े हुए सदस्य तथा समाज के लिए कुछ करने की भावना रखने वाले सदस्यों की भावना, अनुभव, ज्ञान विशेषज्ञता का लाभ शिक्षा जगत को दिलाये जाने के प्रयास हैं"[6]।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किए गए एक अन्य गंभीर अध्ययन में शैक्षिक परिदृश्य में आने वाले कुछ सकारात्मक महत्वपूर्ण और आधारभूत बदलावों की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में 'NO SILOS'(2024)[7] नामक अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 को शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत बदलाव का कारक बताता है। "Paradigm shift: The interconnectedness of policy aspects we like to say it this way: living organisms interact with each other and their natural and physical environment all the time. Being part of the same ecosystem, the bring stability and balance to the whole envrironment. Just like nature all aims of education are interconnected with all aspects of education and depend upon one other to make them holistic and balanced"8. अपने सिद्धांत को तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए यह अध्ययन आगे बताता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के आधार पर शिक्षा प्राप्त शिक्षार्थी अब स्वयं का विकास साक्षर, शिक्षित, रोजगार अथवा स्वरोजगार परक मनुष्य के रूप के साथ–साथ सामाजिक एवं संवेदनात्मक मनुष्य के रूप में भी कर सकेगा।

"**Shift from-** Social and emotional learning SEL skills not an era of focus."

"**Shift to-** Holistic learning including the development of social and environmental learning SEL skills is the focus. It will allow students to build self awareness and positive realtionships develop empathy and understanding for others and see the interconnectedness of different communities and cultures."[9]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 ने शिक्षा को सामाजिक सरोकारों, संवेदनात्मक साहचर्य एवं पारस्परिकता से जोड़ कर शिक्षा के फलक को विस्तार दिया। हालाकि दुनिया भर सहित भारत के के कई विचारकों और शिक्षा शास्त्रियों ने भी विभिन्न माध्यमों से इस बात को सामने रखा था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 का सकारात्मक पक्ष यह है कि वह अपने द्वारा प्रस्तावित सुझावों

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.103

के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। "Para 27-2 of the NEP makes a very crucial and non negotiable statement- By non negotiable we mean it is not open for debate or modifiable: comprehensiveness in implementation will be key; as this policy is interconnected and holistic, only a full length implementation and not a piecemeal one, will ensure that the desired objective are achieved."[10]

इस विश्लेषण को पढ़ते ही हमें 1960 प्रकाशित एस.ओ. नील की पुस्तक 'समरहिल' में एरिक फ्रॉम के लिखे हुए उस प्राक्कथन की याद आती है जिसमें समरहिल की उस अद्भुत प्रणाली का विश्लेषण करते हुए वे कहते हैं, ''शिक्षा में सिर्फ बौद्धिक विकास का पर्याप्त नहीं है। शिक्षा बौद्धिक के साथ भावनात्मक भी हो यह जरूरी है। आधुनिक समाज में बुद्धि और भावना में अंतर क्रमशः बढ़ता जा रहा है। आज मानव के अनुभव उसकी आंतरिक भावनाओं से, आंखों से देखकर, या कानों से सुनकर नहीं होते, वह अनुभव मुख्यतः दिमागी होते हैं। बुद्धि और भावनाओं का यह फैसला व्यक्ति में ऐसी खंडित मानसिकता पैदा करता है जो उसे वैचारिक अनुभव ही पाने देता है।''11 इसका अध्ययन करने की पश्चात हम यह समझ लेते हैं कि आगामी भविष्य में यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 अपने उद्देश्यों में सफल रहती है तो विद्यार्थी को एक सर्व समावेशी पाठ्यक्रम एंव शैक्षिक वातावरण प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि हम यह भी देख पा रहे हैं कि लगभग 140 करोड़ के इस देश में कुछ समस्याएं पूर्ववत बनी हुई हैं और भ्रष्ट राजनीतिक एवं नौकरशाही की समस्या उन पूर्ववर्ती समस्याओं को और अधिक प्रश्रय दे रही है।

जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो अध्ययन बताते हैं कि वर्तमान में विद्यार्थियों विशेष कर स्कूली विद्यार्थियों के मध्य शैक्षिक वातावरण को लेकर व्याप्त असमंजस और उत्साहहीनता का एक बड़ा कारण पाठ्यपुस्तकों की अधिक संख्या का होना है। भारतीय संदर्भ में 80 के दशक के बाद हुए अध्ययन बताते हैं कि विद्यालयों के विद्यार्थियों में **'बस्ते का अत्यधिक बोझ'** है। इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि 90 के दशक के पश्चात भूमंडलीकरण एवं मुक्त बाजार व्यवस्था के क्रियान्वयन के साथ ही तकनीकी एवं अन्य विषयों की वृद्धि होती गई। तकनीकी के क्षेत्र से तथा अन्य नवीन विषयों के क्षेत्र से भी विद्यालयी शिक्षा में नवीन विषयों का समायोजन किया जाने लगा। इस सब के कारण विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन क्रमशः बढ़ता गया। इस संदर्भ में एक तरफ जहां विद्यार्थियों के स्कूल बैग में पुस्तकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, वहीं उनके स्कूल की समयावधि में भी वृद्धि होती गई। निश्चित ही यह बात विद्यार्थियों के लिए अधिक दबाव और तनाव का कारण बनी। इस वृद्धि की नकारात्मकता केवल संख्या वृद्धि तक ही नहीं थी अपितु इन नए विषयों की विषय वस्तु भी विद्यार्थियों की स्थानीय रुचि एवं उनकी भाषिक स्थिति के बहुत अनुकूल नहीं थी। इन विषयों के साथ ही साथ सरकारी समितियां द्वारा बनाए गए पुराने विषयों की पाठ्य पुस्तक भी निरंतर अरुचि कर बनी रही। पाठ्यपुस्तकों में भाषा के कथित परिमार्जित रूप एवं तत्सम प्रधान भाषा ने विद्यार्थियों की अरुचि को और आगे बढ़ाया। शिक्षा के आधारभूत पहलुओं की स्थिति का अध्ययन करते हुए श्री अक्षय कुमार ने लिखा, "स्कूली पुस्तकों का निर्माण मुख्य रूप से केंद्रित तरीके से होता है पुस्तकों के विषय प्रसंग बच्चों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के अनुरूप नहीं है। इस कारण

स्कूली पाठ्य पुस्तकें रुचिकर नहीं लगती हैं। इन पुस्तकों में बच्चों के जीवन मूल्य की झलक नहीं पाई जाती है। बच्चे इन पाठ्य पुस्तकों के विषय प्रसंग को आत्मसात करने की स्थिति में नहीं है। उन्हें अधिक अभ्यास करना पड़ता है जिसके कारण वह पढ़ाई से भागने को मजबूर है"[12]।

यहाँ थोड़ा ठहर कर पाठ्य पुस्तक से संबंधित एक अन्य कोण पर भी विचार करना आवश्यक है। यहाँ पर कह देना भी आवश्यक है कि 70 एवं 80 के दशकों में अमेरिकी शिक्षा शास्त्री John Holt (1923–1985) सहित दुनिया के कई प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों ने तथा इनसे प्रेरणा लेकर भारतीय संदर्भ में शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने 90 के दशक में स्कूली शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों को कम करने के विचार पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की थी। जॉन होल्ट की प्रसिद्धि तो Unschooling जैसे सिद्धांत पर आधारित थी ही प्रोफेसर कृष्ण कुमार एवं उनके कई वरिष्ठ एवं परवर्ती सहयोगियों ने भी पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल दिया था। इनका कहना था, स्कूली शिक्षा में स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय पर्यावरण एवं पारस्परिकता पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

"शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करने के ढंग में देखने में आता है। कुछ शैक्षिक प्रणालियों में इस बात का निर्णय शिक्षक करता है कि बच्चे पाठ्यपुस्तक का सहारा कब लेंगे। वह खुद अपना पाठ्यक्रम और आकलन का तरीका तैयार करता है। वही तय करता है कि वह छपी हुई या अन्य किस्म की कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करेगा। उसके पास शिक्षण की जो विविध सामग्री उपलब्ध होती है, पाठ्यपुस्तक उनमें से मात्र एक प्रकार की सामग्री होती"[13]। हालांकि भारत सहित विश्व भर में ऐसे हजारों प्रयोग होते रहे हैं जहां व्यक्तियों, शोधार्थियों, विद्यालयों एवं संस्थाओं ने पाठ्यपुस्तक रहित शिक्षण के सफल कार्यक्रम संपन्न किए, परंतु फिर भी इस तरह के शिक्षण को प्रयोगवादी एवं द्वितीय श्रेणी का शिक्षण ही माना जाता रहा है। दुर्भाग्यवश यह नकारात्मक तथ्य भारत के संदर्भ में और भी अधिक स्पष्ट है[14]। इसके पीछे के कारण स्पष्ट ही हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को माना जा सकता है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने माना है कि स्कूली शिक्षक में पाठ्य पुस्तक की इतनी और ऐसी अनिवार्य उपस्थित औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन की आंतरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुई थी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस औपनिवेशिक या उत्तर औपनिवेशिक मानसिकता के कारण न केवल बनी रही अपितु और अधिक मजबूत होती रही। 1854 में औपनिवेशिक शासकों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए[15] –

1. "प्राइमरी स्कूल से लेकर ऊंची कक्षाओं तक हर स्तर पर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों की विशेष सामग्री तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण समेत सभी पहलुओं में नई प्रणाली पर नौकरशाही का नियंत्रण होगा।
2. नई प्रणाली का लक्ष्य भारतीय बच्चों और युवाओं को यूरोपीय मनोवृति और दृष्टिकोण के अनुरूप डालना और उन्हें वे कौशल प्रदान करना होगा जो उपनिवेशी प्रशासन विशेष कर इसकी मध्यम और निचली श्रेणी में काम करने के लिए आवश्यक होंगे।
3. अंग्रेजी की पढ़ाई और अंग्रेजी का पढ़ाई के माध्यम के रूप में इस्तेमाल उन्हें इस प्रकार ढालने की क्रिया एवं प्रशिक्षण का जरिया होगा।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.103

4. अगर देसी स्कूल उपनिवेशी सरकार की वित्तीय सहायता चाहते हैं तो उन्हें उनके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के अनुसार शिक्षा देनी होगी।
5. अव्यक्त केंद्रीकृत इम्तिहानों का प्रयोग अगली कक्षा में तरक्की और वजीफे के लिए छात्रों की योग्यता परखने के वास्ते किया जाएगा"[16]

हजारों साल पुरानी सभ्यता वाली शिक्षा व्यवस्था के लिए ये बदलाव बिलकुल चौंका देने और भ्रमित करने वाले थे। सामान्य भारतीय जनमानस, सामंतों, राजाओं, शासकों, पुरोहित या परम्परागत शिक्षकों ने कभी ऐसा कुछ देखा सुना नहीं था। पाठ प्रधान शिक्षा व्यवस्था होने पर भी भारतीय शिक्षा ने पाठ्यपुस्तक का ऐसा एकछत्र राज और वह भी नौकरशाही की छाया तले, कभी अनुभव नहीं किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और विषय–वस्तु की नवीनता भी परम्परागत शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण थी। इन सभी कारकों ने मिल कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्परा और पर्यावरण से अलग कर दिया। अब शिक्षित व्यक्ति की मानसिकता से स्थानीय समस्याएं और परम्परागत पामान्वीत पारिस्थिकी एकदम बहार हो गई और वह औपनिवेशिक शासन का एक जीवित पुर्जा बन गया। दुर्भाग्यवश धीरे–धीरे औपनिवेशिक सामाजिकी और आर्थिकी मात्र से प्रेरित शिक्षा व्यवस्था ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एकमात्र विकल्प बन गया जो समय के साथ साथ अपने आन्त्रिकी रूप को और मजबूती से स्थापित करता रहा। स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा व्यवस्था की भीतर यह विकल्पहीनता बनी रही। ''शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान के ढाँचे एक बार बन जाएँ तो आसानी से बदलते नहीं। अंग्रेजों की दी हुई शिक्षाप्रणाली उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई, और आजाद भारत में भी पाठ्यक्रम पाठ्यपुतकों से बंधा रहा। आजादी के बाद से शिक्षा प्रणाली में प्रसार तो बहुत हुआ है, फिर भी उसे पाठ्यपुस्तके लागू करने और इम्तिहानों की अंग्रेजी नीतियों से छुटकारा नहीं मिल पाया है"[17]।

लेकिन धीरे–धीरे औपनिवेशिक मानसिकता के कारकों की पहचान होती रही है। भारतीय स्वाधीन चेतना और स्वदेशी अस्मिता ने राष्ट्रीय और स्थानीयता के महत्त्व को पहचाना है और शिक्षा व्यवस्था के आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन किए हैं। स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्पराओं और सम्पूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी को शिक्षा के मूलभूत कलेवर में स्थान मिले है तथा पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक सरोकारों और प्रयोगात्मक शिक्षा को संबल प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह अनुभव किया जा सकता है कि एक शिक्षित व्यक्ति की मानसिक संरचना में स्थानीय समस्याओं को स्थान मिला है। कहना ना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस समस्या को बहुत गहराई से हल करने के प्रयासों को प्रेरित किया है जिसके फलितार्थ निश्चित ही दूरगामी होंगे।

संदर्भ

1. कृष्ण कुमार, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, प्रथम हिंदी संस्करण 1998, पुनर्मुद्रण 2013, ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली पृ० सं०–11
2. उपरोक्त, पृ० सं०–29
3. उपरोक्त, पृ० सं०–31

4. अतुल कोठारी (सं) राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 भारतीयता का पुनरुत्थान, 2024, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पृ० सं०–12
5. अतुल कोठारी (सं) राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 भारतीयता का पुनरुत्थान, 2024, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पृ० सं०–41
6. उपरोक्त, पृ० सं०–146
7. विस्तृत अध्ययन के लिए देखें– Anita Karwal, Rashi Sharma, and Rajnish Kumar, NO SILOS LEARNING THE NEP WAY, 2024, National Book, trust New Delhi.
8. Anita Karwal, Rashi Sharma, and Rajnish Kumar, NO SILOS LEARNING THE NEP WAY, 2024, National Book, trust New Delhi, पृ० सं०–149
9. उपरोक्त, पृ० सं०–150
10. उपरोक्त, पृ० सं०–151
11. ए.एस. नील – समरहिल, हिंदी अनुवाद– पूर्वा याग्निक कुशवाहा, प्रथम संस्करण– 1960, हिंदी संस्करण– 2017, एकलव्य प्रकाशन, भोपाल, मध्य प्रदेश, पृ० सं०–10)
12. अक्षय कुमार– शिक्षा की मुक्ति, 2006, ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली, पृ० सं०–51– 52
13. कृष्ण कुमार, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, पुनर्मुद्रण, 2013, ग्रंथ शिल्पी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, पृ० सं०–83
14. इस संदर्भ में यदि पाठक श्री सुनील जोशी की लिखित पुस्तक 'जश्ने तालीम होशंगाबाद विज्ञान का शैक्षिक सफरनामा' जिसका प्रकाशन अगस्त 2008 में एकलव्य प्रकाशन, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है का अध्ययन करेंगे तो बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।
15. भारत में स्कूली शिक्षा के पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित होने का सम्बन्ध उन ऐतिहासिक परिस्थितियों से है जिनमें भारत की वर्तमान शिक्षा–प्रणाली का विकास हुआ। यदि बारीकी से देखा जाए तो पाठ्यपुस्तक की संस्कृति कि शुरुआत उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारभ में देखी जा सकती है जब ईस्ट इडिया कम्पनी ने भारत की शिक्षा प्रणाली गढ़ने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए। इस नई प्रणाली को 1854 में सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच के जरिए नौकरशाही आकार मिला। कृष्ण कुमार, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, पुनर्मुद्रण, 2013, ग्रंथ शिल्पी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, पृ० सं०–85–86
16. उपरोक्त, पृ० सं०–86
17. उपरोक्त, पृ० सं०–97